International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 08-01-2022, Accepted: 07-02-2022, Published: 22-02-2022
Volume 8, Issue 1, 2022, Page No. 172-174

भारत में काले धन की समस्या एवं प्रभाव

डॉ. बलभद्र प्रसाद देवांगन[1], डॉ. पुश्पा देवांगन2
[1] प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, अशोका महाविद्यालय, उम्मेदपुर, सारंगढ़, छत्तीसगढ़, भारत
[2] प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, के. पी. महाविद्यालय, बंधापाली सारंगढ़, छत्तीसगढ़, भारत

सारांश
भारतीय अर्थव्यवस्था संकट के काल से गुजर रही है। वर्तमान में जनसंख्या, बेरोजगारी, निर्धनता, मंहगाई, ग्रामीण विकास शहरीकरण तथा समानान्तर अर्थव्यवस्था, का संचालन आदि समय की चुनौतियां बन गई है। इनमें जनसंख्या वृद्धि तथा समानान्तर अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से बुरी तरह हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। यह समानान्तर अर्थव्यवस्था ही काले धन का जाल है, कुछ लोग इसे गुप्त अर्थव्यवस्था, भूमिगत अर्थव्यवस्था एवं छिपी हुई अर्थव्यवस्था भी कहते है। यह सर्वविदित है कि अरबों मात्रा में मुद्रा, आय तथा सम्पतियां बिना लेखे के है, जो कि हमारी कर प्रणाली में प्रदर्शित नहीं की जाती है, बनाई जा रही है तथा संचय की जा रही है। इस बिना लेखे की आमदनी का उपयोग वैज्ञानिक तथा गैर वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में यह काला धन कई वर्षों से पैदा हो रहा है तथा इसके विभिन्न आयाम है जो हमारी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन को कई तरह से प्रभावित कर रहा है। वास्तव में यह काले धन की समस्या हमारी अधिकारिक मौद्रिक व्यवस्थां के लिए एक चुनौती बन गया है। तथ्य यह है कि यह काले धन की समस्या समाज के प्रत्येक क्षेत्र में तथा अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में विद्यमान है तथा कुचक्र के रूप में संचालित होता है।

मुख्य शब्दः अर्थव्यवस्था, करारोपण, मुद्रास्फिति, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक निति, मुद्रा का विमुद्रीकरण

हमारे देश में कुल कितना काला धन विद्यमान है इसके लिए कई प्रयास किये गये व सभी प्रयासों में इसकी विद्यमानता तथा गम्भीरता को स्वीकार किया गया है, परन्तु मात्रात्मक आंकलन के बारे में एक राय नहीं है। एक अधिकारिक अनुमान | जो National Institute of Public Finance & Policy द्वारा किया गया है, उसके अनुसार टैक्स से बचाई गई आमदनी 1975–76 में 2467.4 करोड़ से 3740.7 करोड़ के बीच थी जो बढ़कर सन् 2014–15 में 14838. 94 करोड़ से 19843.08 करोड़ की हो गई। राजा जे, चौल्लये की कमेटी ने अनुमान लगाया है कि भारत में GDP का 20 प्रतिशत की दर से काले धन का निर्माण हो रहा है। वर्तमान में अनुमान है कि हमारी अर्थव्यवस्था में लगभग 30–40 प्रतिशत रूपया इसी काले धन का विद्यमान है। काला धन कितना है इसका अधिकारिक मात्रात्मक स्वरूप क्या है, यह विवाद का विषय हो सकता है, परन्तु इसकी उपस्थिति तथा इसके कुचक्र को सभी स्वीकार करते है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में काला धन उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण है:

1. करारोपण का ढाँचा तथा उसका लेवल है। भारत में आज भी कहा जाता है कि प्रत्यक्ष कर जिसमें विशेषतः आयकर शामिल है कि करारोपण दर आज भी ऊँची है। यद्यपि पिछले वर्षो में इसके लेवल को कम किया गया है। कर चोरी भारतीय अर्थव्यस्था में एक आम बात हो गई है। यह एक मनौवैज्ञानिक तथ्य है कि कर की चोरी करना आसान हो तो व्यक्ति इसका अवश्य सहारा लते है। 400 रूपये कमा कर 30 रूपये टैक्स देने की तुलना में व्यक्ति 30 रू. की टैक्स चोरी जो आसानी से हो सकती हो तो व्यक्ति कर चोरी का रास्ता चुनना पसंद करता है।
2. दूसरा सबसे बड़ा कारण सार्वजनिक व्यय के कार्यक्रम है। भारत में बड़ी मात्रा में सार्वजनिक व्यय सरकार द्वारा किये जाते है, लेकिन दुर्भाग्य से उन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा प्रशासन में कई प्रकार की कमियाँ होती है। इनका दूषित प्रशासनिक पहल तथा कमजोर डिजायन इसके लिए जिम्मेदार है। इन सार्वजनिक व्यय कार्यक्रमों में कई गैर कानूनी कमियाँ होती है जिसके कारण बड़ी मात्रा में सार्वजनिक बचत को ये सार्वजनिक व्यय के कार्यक्रम खत्म कर देती है।
3. तीसरा बड़ा कारण देश में मुद्रास्फिति का होना है। मुद्रास्फिति तथा मंहगाई के कारण व्यक्ति की वास्तविक आय उसे कम लगती है तथा अपने जीवन स्तर को बनाये रखने के लिए वह गैर कानूनी तरीके से टैक्स की चोरी करने लगता है। इसके अतिरिक्त बेमानी व्यवहार भी बहुत होते हैं जिसके कारण टैक्स चोरी होती है। मुद्रास्फिति तथा महंगाई की मार कठोर परिश्रम से अर्जित करने वाले वेतन तथा मजदूरी प्राप्त करने वाली लोगों पर पड़ती है। इसमें राज्य कर्मचारी भी शामिल है। यह वर्ग अपनी अधिकारिक पोजीशन का दुरूपयोग करने लगते हैं तथा घूसखोरी तथा रिश्वत आदि का सहारा लेने लगते है जिसके कारण देश में बड़ी मात्रा में काला धन पैदा हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्र में वातावरण दूषित हो रहा है।
4. चौथा कारण राजनैतिक चंदे है। आज कोई भी राजनैतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो राजनैतिक चंदे वसूल न करती हो। अक्सर ये चंदे कर चोरी से बचाई गई आमदनी से दिये जाते हैं। भारतीय निर्वाचन प्रणाली आज इतनी खर्चीली तथा व्यय साध्य है कि कोई भी व्यक्ति बिना कालेधन की सहायता के चुनाव नहीं लड़ सकता। विभिन्न विशेषज्ञ समितियों ने बताया है कि चुनावों में काफी बड़ी मात्रा में कालेधन का प्रयोग किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि यह काला धन दुबारा से फिर समाज में आकर अपना रूप दिखाता है, जिसके कारण एक ऐसा ताना–बाना बन जाता है जिसमें

आम नागरिक से लेकर अधिकारी, व्यापारी तथा राजनेता सभी उलझ जाते हैं जो बाद में जरूरत पड़ने पर एक–दूसरे की गैर कानूनी तरीके से मदद भी करते है।

5. पांचवा कारण गिरता हुआ नैतिक स्तर है। आज समाज में प्रत्येक सत्र तथा प्रत्येक क्षेत्र में नैतिक मूल्यों का हास हुआ है। झूठ बोलना, धोखा देना, चोरी करना, घूसखोरी तथा रिश्वत लेना आदि आम बात हो गई है। वाचू कमेटी तथा अन्य कई विशेषज्ञों ने काले धन की उत्पत्ति तथा स्टॉक के लिए नैतिक मूल्यों में तेजी से होने वाली गिरावट को काले धन के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जिम्मेदार माना है। वास्तव में भारत में कर चोरी के लिए धनिक वर्ग, अधिकारी तथा सरकारी कर्मचारी तथा राजनेता विशेषतः जिम्मेदार है। दुर्भाग्य से इन तीनों वर्गों में इस काले धन का एक ऐसा जाल फैला हुआ है जो दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है। इसके कारण एक ओर अमीर और अमीर हो रहे हैं तथा दूसरी ओर सत्ता का विकेन्द्रीकरण होने के बजाय कुछ लोगों के हाथों में इसका संकेन्द्रण होने की प्रवृत्ति को बल मिला है। इस प्रवृत्ति के गंभीर परिणाम हमारी अर्थव्यवस्था में साफ दृष्टिगोचर होने लगे है।
6. छठवां कारण गैर कानूनी स्थायी सम्पत्तियाँ भी काले धन को बढ़ावा देती है, जैसे– स्थायी सम्पत्ति को खरीदते या बेचते समय उसकी कीमत का कम मूल्याकंन किया जाता है। इसी प्रकार व्यापारिक इमारतों को प्राप्त करने के लिए उसके मालिकों को पगड़ी के नाम पर एक मुश्त राशि देनी पड़ती है जिसका कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है, इससे भी काले धन को बढ़ावा मिलता है।
7. सतवां कारण भारत में राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों, ठेकेदारों के बीच के गठजोड़ ने भ्रष्टाचार को एक संगठित तन्त्र बना दिया है। विशेषज्ञों के एक आँकलन के अनुसार भारत में भ्रष्टाचार एक उद्योग का स्वरूप ले चुका है, जिसका आकार एक अरब डालर (कालाधन) से अधिक है।

कालेधन का प्रभाव

इस काले धन के जाल का परिणाम यह हो रहा है कि एक ओर सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व की हानि हो रही है जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ा है। अधिक आय प्राप्त करने के लिए सरकार नये कर लगातो है जिससे फिर कर चोरी को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार करों की चोरी और नये कर लगाने अथवा पुराने करों में वृद्धि का विषम चक्र निरन्तर चलता रहता है जिससे सरकार तथा आम जनता को असुविधा होती है। भारत में इसी प्रकार की कमोबेश स्थिति बन गई है। कर चोरी का सबसे अधिक लाभ धनिकों तथा प्रभावशाली वर्गों को मिलता है जबकि ईमानदार तथा कानून का पालन करने वाले व्यक्ति को पूरा कर चुकाना पड़ता है। भारत में जब–जब कर बढ़ाये जाते हैं इसकी सबसे बड़ी मार नौकरी पेशा लोगों अथवा मध्यम आय वर्ग के लोगों पर पड़ता है। इन लोगों को कर चोरी के साधन उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार करों की चोरी अन्याय को जन्म देती है। आर्थिक आधार पर न्याय नहीं मिलने के कारण यह मध्यवर्गीय तबका अन्य गलत तरीकों का उपयोग करने लगता है। भारत में तो अब यह कहावत सी बन गई है, कि भले और ईमानवार व्यक्ति ही पूरा कर है। इस काले धन का एक और परिणाम आर्थिक एवं सामाजिक विषमता फैलाने का होता है। कर चोरी करने वाला उच्च धनिक वर्ग प्रायः समाज में नये तथा घिनौने वातावरण को जन्म देता है। उनके निवासों में सम्पत्ति का अहम् प्रदर्शन किया जाता है तथा शादी–विवाह व अन्य उत्पादों पर अपार धन खर्च किया जाता है। उनके रहन–सहन के स्तर में विदेशीपन की दुर्गन्ध आने लगती है। इनका जीवन ऐसा आराम एवं विलासितापूर्ण हो जाता है। मदिरापान, जुआ खेलना, औरतों का शोषण तथा समाज और सरकार के कानूनों से खेलना इनकी आदत सी बन जाती है। इन लोगों के चारों ओर धन पिपासा में पीड़ित तथा मजबूरी के मारे लोग भौरों की तरह मंडराने लगते है और समाज में पिट्टठूवाद तथा चमचागीरी की अवांछनीय प्रवृत्तियों को बल मिलता है। काले धन के परिणामस्वरूप कुछ एक व्यक्तियों के आस–पास सम्पत्तियां हो जाती है। इस धन बल का अनुचित, अनैतिक, अवैधानिक तथा अवांछनीय प्रवृत्तियों में व्यय होता है जिससे सरकार की आर्थिक नीतियों की सफलता संदिग्ध हो जाती है। सरकारी तंत्र बुरी तरह असफल तथा लाचार हो जाता है। भारतीय नियोजन को वांछनीय सफलता नहीं मिलने का एक बड़ा कारण यह भी है। सरकारी धन साधनों के एकत्रीकरण को एक ओर धक्का लगता जबकि दूसरी ओर आय वितरण के सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। भारतीय मौद्रिक नीति तथा राजकोषीय नीति की सफलता संदिग्ध हो जाती है। रिजर्व बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा संचालित नीतियों कारगर सिद्ध नहीं हो पाती है। वास्तव में कर वंचना के लिए उत्तरदायी लागे भारत की आर्थिक नीतियों की सफलता में बाधक रहे हैं।

भारत में पिछले 75 सालों में इस समस्या की गंभीरता पर विचार किया गया है परन्तु कारगर तथा उत्साहजनक परिणाम प्राप्त नहीं किये जा सके है। अब तक जो कार्य काले धन को रोकने के लिए किये गये उनमें मुद्रा का विमुद्रीकरण [Voluntary Disclosure Scheme (VDS) Raids, तथा स्पेशल वियरर बॉड स्कीमें कोई अच्छा परिणाम नहीं दिखा सकी है। केवल मात्र समय – समय पर सरकार द्वारा डाली जाने वाली त्पके का अवश्य भय रहता है परन्तु दुर्भाग्य से तथा कानूनी कमियों तथा खामियों के चलते ये Raids भी कारगर सिद्ध नहीं हो रही है।

सुझाव एवं निष्कर्ष

वास्तव में भारत में काले धन की समस्या एक ऐसा मर्ज बन गया है जिसका जितना इलाज किया जाता है उतना ही बढ़ रहा है। जैसे–जैसे मर्ज बढ़ता गया वैसे–वैसे उपचार किया, वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। इस काले धन के जाल को तोड़ने के लिए सरकार की इच्छाशक्ति, जनता का सहयोग और सरकारी तंत्र की ईमानदारी तथा नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था पैदा करने की जरूरत है। सरकार को करों का निर्धारण तथा आंकलन को सरल एवं कर प्रणाली को कुशल बनाने के लिए भागीरथ प्रयत्न करने चाहिए। करों की दरों को उचित स्तर पर बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। विभिन्न करों को युक्ति संगत बनाना आवश्यक हो गया है। धन के अनावश्यक प्रदर्शन पर रोक लगाना भी उचित होगा तथा इस कार्य के लिए कठोर दण्डात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। केवल आर्थिक दण्ड से धन तथा प्रदर्शन की प्रवृत्ति पर रोक लगाना असम्भव नहीं तो मुश्किल अवश्य है। भूमि, भवन तथा अन्य वैभव पूर्ण कार्यो पर चौकस कड़ी करनी चाहिये तथा गैर कृषकों की सम्पूर्ण भूमि तथा परिवार की आवश्यकता से अधिक भवनों तथा मकानों और खाली प्लाटों को

सरकार द्वारा अधिगृहीत कर लेना चाहिए, परन्तु हमारे देश में इस प्रकार का निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना बहुत मुश्किल है, क्योकि सत्ता पक्ष तथा विपक्ष दोनों ही तहें दिल से यह नहीं चाहते कि इस प्रकार कठोर निर्णय लेकर जनता की नाराजगी मोल ली जाये। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गुनार मिर्डल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एशियन ड्रामा में महत्वपूर्ण तथा बड़े ही प्रभावी ढंग से वर्णन किया है कि अधिकांश विकासशील देशों में प्रशासन व्यवस्थाएं ढीली तथा लचीली है, जिसके कारण इन देशों में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पक्षपात और भाई–भतीजावाद का बोलबाला रहता है। वास्तव में भारत में भी प्रशासनिक शिथिलता इस काले धन की समस्या के लिए जिम्मेदार है परन्तु जनता भी कम दोषी नहीं, क्योकि लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा ही चुनी जाती है।

संदर्भ सूची

1. लक्ष्मीनारायण एवं राम नाथू (2000) भारतीय अर्थव्यवस्था, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, संस्करण।
2. सिन्हा, वी.सी. (2008) व्यावसायिक पर्यावरण, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, संस्करण।
3. मिश्र एवं पुरी (2000) भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
4. नाग, डी. एस. (1984) अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की समस्याएं शिक्षा, साहित्य प्रकाशक, आगरा।
5. दत्त, रूद्रय सुन्दरम, के. पी. एम. (2001) भारतीय अर्थव्यवस्था, एस. चंद एंड कम्पनी राग नगर, दिल्ली।
6. गुप्ता, एस. सी. (1999) आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था, एजुकेशनल पब्लिशर्स, जयपुर।
7. भटनागर, कालका प्रसाद (2002) भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किशोर पब्लिशिंग हाउस, कानपुर, संस्करण।